

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 14 फरवरी, 2012

विषय :- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य के पेयजल विहीन 30 विद्यालयों को पेयजल से संतृप्त किये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

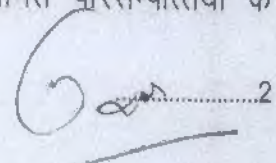
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7418/अप्रै0-03/विद्यालय पेयजल व्य0/2011-12 दिनांक 18.01.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 631/2004 दिनांक 29.04.2011 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में राज्य के पेयजल विहीन 30 विद्यालयों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित आगणनों की कुल धनराशि ₹ 134.51 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या 1055/उन्तीस(2)/11-2(30पे0)/टी0सी0-V दिनांक 11.08.2011 के द्वारा पूर्व में अवमुक्त 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 53.80 लाख के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय किश्त की लागत के 40 प्रतिशत अर्थात् ₹ 53.80 लाख (₹ तिरेपन्न लाख अस्सी हजार मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान धनराशि आहरण के पश्चात प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम को उनके द्वारा संतृप्त किये जाने वाले विद्यालयों हेतु धनराशि अपने स्तर से हस्तान्तरित करेंगे। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. शासनादेश की अन्य शर्तें एवं विद्यालयों का विवरण पूर्व निर्गत शासनादेश के अनुरूप ही रहेगा। समयान्तर्गत सम्बन्धित विद्यालयों को पेयजल से पूर्ण रूप से संतृप्त करते हुए शासन एवं निदेशक, विद्यालयी शिक्षा को भी आवश्यक रूप से अवगत कराया जाय। कार्य अनुमोदित आगणन के सापेक्ष ही किया जाना होगा। अर्थात् आगणन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-आयोजनागत -102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-ग्रामीण पेयजल सेक्टर-00-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।



5 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं०- 64/XXVII (2)/12
दिनांक 07 फरवरी, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी०बी० ओली)

संयुक्त सचिव

पृ०सं० 146 (1) /उन्तीस (2)/12-2(30पे०)/2011 टी०सी०-V तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
11. स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा सैकली)

उप सचिव